

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जहांगीर बनाम इशब वगै.

घाटा-212
य.का.आधी.

नया व तारीख
अहकाम जो हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

पत्रावलि प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घाटा-212 राज. कारतकारी अधिनियम पर दिनांक 13.11.2018 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण इशब वगै, को जदिये अन्तरिम अस्थायी निर्दिष्टाता पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 14.12.2018 तक आ.ख.न. 155/091, 172/066, 28/077 बाँके गाम नीमकी, तह.नगर पर रहन वय मुन्नकिल नही करे, खायल को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल नही करे, मजाहमत मदाज्जल नही करे, जोतने बौने से नही सेके, मौका व राजस्व बिकार को यथासिध्द बनाये रखे।

इसके पश्चात आगामी तारीख पेशियों तक अन्तरिम अस्थायी निर्दिष्टाता प्रयुक्त रही।

प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी व. 1 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जो शाखिले पत्रावलि किया गया। अप्रार्थी व. 2 को जवाब प्राप्त करना नहीं चाहते है।

प्रार्थना पत्र पर बहस खुली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि विवाहित आराजी पेटुक आराजी है जिनमें मैंने हिस्से का दावा किया है, दावा निर्णित होने तक अस्थायी निर्दिष्टाता को संपुष्ट किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कहा कि दावे व प्रार्थना पत्र में पसकार समान नहीं बनाये गये है, वादी, प्रतिवादी भेव यानी इमिलय समुदाय से है जिनमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की त्रॉती पेटुक आराजी में दावा लाने का अधिकार नहीं है। स्वयं की कब्जे कारत खतरेही आराजी होने के आगामी निर्दिष्टाता खाडिज फले का कथन किया। नज़रिं RRT 1987 P. 1275, RRT 1988 P. 563, RRT (12) 2005 P. 345, RRT (20) 2013 P 96 उल्लेख किये।

पत्रावलि का समग्र दखलन/हावलोकन किया। गजियों का भी दखलन किया। इसके उपरान्त इस निर्दिष्टाता पर पहुँचते है कि -

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आराजी पेटुक आराजी किस प्रकार से है तथा इसका कितना हिस्सा आराजी में होना चाहिए, आराजी



के पैगुड होने संबंधी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य-
पान्तविक्रम भी उत्पन्न नहीं किया गया है। इससे पृथक्
दृष्ट्या वाद होना स्पष्ट नहीं होता है।

- वर्तमान रातान डिपोर्ट जमाकरी ब. 2012-75 में
अपार्थी ब. 1 एक खतेदार के रूप में दर्ज है एवं
उपार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं करने से कि डिपोर्ट आदेश
किस प्रकार से पैगुड कराया है तथा इस आधार पर
उसका संग्रहित दित (दिमा) किना होना चाहिए,
एक डिपोर्ट खतेदार के पक्ष में सुविधा का संगुलन
समाहित होता है।

- स्वयं अपार्थी को अपने दिनों की स्पष्ट जानकारी
न होने तथा एक संग्रहित पत्रिकल्पना के बाध पर
ही उसे अपूरणीय शक्ति हो सकती है, स्वीकार नहीं
होता है।

इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक
13.11.2018 को जारी किये गये अन्तर्निम अन्वेषण
विधेयता के आदेश को जारी रखा जाना न्यायालय
न्यायोचित नहीं समझता है तथा अपार्थी के वाचन
पर अन्तर्गत धारा-212 राज. कार्यकारी कार्यक्रम को
जांचकर करते हुए पूर्व दिनांक 13.11.2018 को जारी
अन्तर्निम अन्वेषण विधेयता आदेश को निरस्त
किया जाता है। निष्कर्ष के तहत आज दिनांक
10.3.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में
दुनाया गया।

10.3.24

(सुरेन्द्र प्रसाद)